

वीर परिवार सहायता योजना

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में 26 जुलाई 2025 को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर श्रीनगर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने वीर परिवार सहायता योजना 2025 शुरू की गयी है, जो सैनिकों, पूर्व सैनिकों, और उनके परिवारों को निःशुल्क कानूनी सहायता, सलाह एवं प्रतिनिधित्व प्रदान करेगी।



‘VEER PARIVAR SAHAYATA YOJANA’

उद्देश्य:

- इस योजना के माध्यम से सैनिकों और उनके परिवारों को न्यायिक सहयोग, विधिक सलाह, और केस प्रतिनिधित्व की सेवाएँ प्रदान की जाएंगी। यह योजना उनके लिए डिज़ाइन की गई है, जिनके पास दूरस्थ स्थानों या सीमावर्ती क्षेत्रों में कानूनी सहायता तक पहुंचने की सुविधा नहीं है।

संवैधानिक और संस्थागत आधार

- इस योजना का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 39A (समान न्याय एवं कानूनी सहायता) है।
- NALSA 1995 में Legal Services Authorities Act, 1987 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है जो कानूनी सहायता कार्यक्रमों का समन्वय करता है।

कार्यान्वयन संरचना:

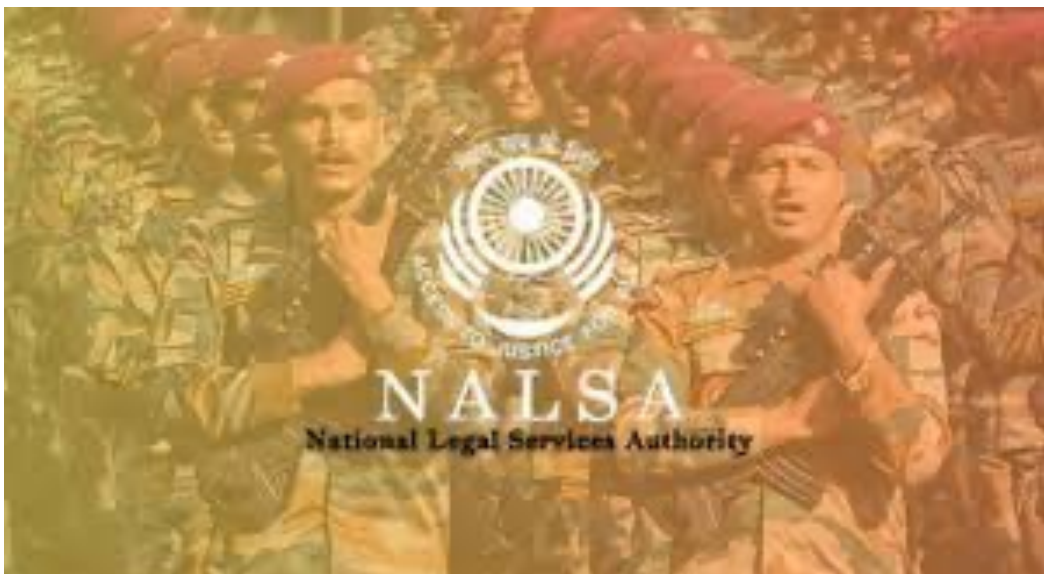
- **क्रियान्वयन:** इस योजना का कार्यान्वयन राज्य और जिला सैनिक बोर्डों में स्थापित लीगल सर्विसेज क्लीनिक के माध्यम से किया जाएगा। इन क्लीनिक में panel lawyers और para-legal volunteers मौजूद होंगे, जो सैनिकों और उनके परिवारों को कानूनी सहायता प्रदान करेंगे।
- **Volunteers:** छात्र-सैनिक परिवार स्वयं paralegal volunteers बन सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूक्ष्म स्तर पर भी मदद पहुँच सके।

पहुँच और लाभार्थी वर्ग:

- **पैन-इंडिया कवरेज:** यह योजना सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कार्यान्वित होगी, ताकि समावेशी राष्ट्रीय कवरेज सुनिश्चित हो सके।
- **लाभार्थी वर्ग:** इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले प्रमुख समूह में सक्रिय सैनिक (Army, BSF, CRPF, ITBP, CISF), पूर्व सैनिक और उनके परिवार सदस्य शामिल हैं।

NALSA के बारे में:

- **परिचय:** NALSA (National Legal Services Authority) एक वैधानिक निकाय है जिसे 1995 में Legal Services Authorities Act, 1987 के तहत स्थापित किया गया था। यह संस्था कानूनी सहायता प्रदान करने के कार्यक्रमों का संचालन करती है और विभिन्न समाजिक वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करती है। NALSA की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्गों, जैसे महिलाओं, बच्चों, SC/ST और अन्य समुदायों के लिए कानूनी सेवा प्रदान करना है।



- **कानूनी सहायता अवसंरचना:** NALSA ने तालुक न्यायालयों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक कानूनी सेवा संस्थान स्थापित किए हैं, ताकि न्याय की पहुंच सभी तक हो सके।



UPSC PARACTICE QUE :

- Q. हाल ही में वीर परिवार सहायता योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया था?
- केंद्रीय गृह मंत्रालय
 - भारतीय न्यायालय
 - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)
 - भारतीय सेना

(वैकल्पिक विषय) Result Mito

OPTIONAL SUBJECT

GEOGRAPHY

OPTIONAL

Fee - मात्र 6499 ₹

केवल 21 से 26 जून

50 ऑन कवल 31 से

OPTIONAL SUBJECT Result Mito

वैकल्पिक विषय

PSIR

Fee - मात्र 6999 ₹

केवल 01 से 06 जुलाई

Dr. Faiyaz Sir

01 जुलाई से 06 जुलाई